نہیں ہے اور مذہبی لفظ تو بیس استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن اعتراض ظاہر کرتے ہوئے ہم لوگ واک آؤٹ کر رہے ہیں شکریہ

[-ے

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: madam, I have one apprehension. The statement of the...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We had enough discussion on this. We are going to have a discussion on this on Tuesday also.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I have an apprehension that the office of the Chief Minister will be used to prevent the law from taking its own course. It is not a question of morality only.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Now, we take up Zero Hour submissions. Shri Narendra Mohan, Shri Dawa Lama, Shri Mohd. Azam Khan, Shri Anantray Dev Shanker Dave-Hon. Members absent.

They are really Zero Hour submissions.

RE. LOSS OF LIFE AND PROPERTY DUE TO HEAVY RAINS AND FLOODS IN GUJARAT

श्री अहमद पटेल (गुजरात)—उपसभाध्यक्ष महोदया, पिछले महीने गुजरात में भारी बारिश हुई और उस की वजह से जो तबाही वहां हुई, मैं उस की ओर इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदया, पूरे सीजन में गुजरात में जितनी बारिश होती है, महज चार दिनों में वहां 90 प्रतिशत से ज्यादा बारिश हुई जिस कारण 100 से ज्यादा लोग गुजरात में मारे गए हैं, जीवन-व्यवहार ठप्प हो गया और सैकड़ों लोग बेघर और बेरोजगार हो गए। रेल और सड़कें बंद हो गयीं जिस की वजह से यातायात ठप्प हो गया। 50 से ज्यादा मार्ग बंद हो गए और करीबन् एक हजार करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान राज्य सरकार को हुआ। मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी टीम के साथ गुजरात का दौरा किया। जो अफेक्टिड एरियाज़ है वहां विजिट की ओर उसके बाद कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्होंने अनाउंस किया।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): रामदेव भंडारी जी, अगर आपको बात करनी हो तो आप लॉबी में जाकर बात करिए क्योंकि आनरेबल मैम्बर कुछ बोल रहे हैं।

श्री अहमद पटेल: लेकिन आपके माध्यम से मैं मंत्री होदय और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो नुकसान हुआ है वह बहुत भारी मात्रा में हुआ है, करीबन् एक हजार करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान वहां पर हुआ है। सड़कों की मरम्मत करानी है और उसमें काफी पैसे लग जाएंगे।

मैं मंत्री महोदय से और सैंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध करूंगा कि यद्यपि यह नेचुरल केलामिटी है लेकिन इसको नेशनल केलामिटी और वास्ट केलामिटी कंसीडर करके ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस राज्य सरकार को दी जाए ताकि टूटी हुई सड़कों की मरम्मत हो सके और वहां के लोगों को भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (गुजरात): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपने आपको इनके साथ सम्बद्ध करते हुए कहना चाहती हूं कि पानी से नुकसान बहुत हुआ है और वहां के खेतों में 4-4, 5-5 इंच रेत की परत जम गई है और जमीन इतनी खराब हो गई है कि उसके ऊपर कुछ खेती करना इस समय नामुमकिन है और यह हाल पूरे महसाना और सुरेन्द्र नगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो खेतों से रेत को निकालने के लिए किसानों को कुछ मदद दी जाए, यह बहुत जरूरी है और जो वहां मकान है, गोदाम है, उनमें तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच फुट पानी भर गया है और जो उन्होंने उसमें फसल डम्प करके रखी थी, वह भीग गई है इसमें भी एक-एक गोदाम में दो-दो, तीन-तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह ऐसा एरिया नहीं था, जहां बाढ़ आए इसलिए उन्होंने इन्शोयोरेंस नहीं किया हुआ था। किसानों को वहां जितना नुकसान हुआ है, वह सहन करना मुश्किल है। तो इसके लिए और कोई स्टैप सोचकर उनको कुछ मदद, इन्डायरेक्ट हेल्प के रूप में, दी जाए। या तो उनको कोई स्पेशल लोन देकर बैंक की ओर से कुछ मदद मिले। ऐसा कुछ करना बहुत जरूरी है। सरकार इसके बारे में सोचे और इसका जो असर

हुआ है किसानों पर, किसानों की कोआपरेटिव पर या गोदामों पर, इसके बारे में भी कुछ सोचा जाए। धन्यवाद।

SHRI BRAHMAKUMAR BHATT (Gujarat): Madam Vice-Chairperson, while associating myself with the Zero Hour submission made by my colleague, Shri Ahmed Patel, I just want to say that 220 people have lost their 'lives. I want to bring to the kind notice of the Government that out of 220 persons, 200 persons were the poorest of the poor and were doing some agriculture near the riverbed. Floods have swept away everything, their families, their children and their belongings. On the other hand, the assistance given by the Government till now is only Rs. 55 crores. When there is a damage in thousands of crores of rupees, when 220 persons have lost their lives, this meagre assistance of Rs. 55 crores is not enough. The Government of India should come forward with higher financial assistance to the State Government so that those who have suffered huge losses in agriculture, who have lost their property, who have lost their family members may be given a little more than what was given.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Okay. thank you. Mr. Minister, do you want to say something on this?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): उपसभाध्यक्ष महोदया, जब वहां पर पानी बरसा था और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था तो मैं वहां खुद गया था और मैं महसाना डिस्ट्रिक्ट में भी गया था माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, वह सही है कि बहुत बड़े पैमाने पर वहां बर्बादी हुई है। उस वक्त हमने केलामिटी रिलीफ फंड से करीब 55 करोड़ रुपए वहीं पर दे देने का आदेश दिया था। उस रुपए को खर्च करने के बारे में एक गाइडलाइन यह भी था कि 250 करोड़ रुपए तक या उससे भी ज्यादा, जो वहां बालू भर गया है या सिल्ट आ गया है उसको साफ करने में भी खर्च करें। बाकी हमने सैंट्रल टीम वहां भेज दी है, वे जब असैस करके लाएंगे तब हम नेशनल रिलीफ कमेटी की बैठक बुलाकर, हमारे पास जो कुछ साधन हैं, उनमें से मैं और भी सहायता करूंगा।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल: अगर 55 करोड़ रुपए से सब कुछ मदद करनी है तो सबको मदद नहीं पहुंचेगी। इसलिए इसके बारे में स्पैशल प्रोविजन करने की जरूरत है।

श्री चतुरानन मिश्र: हमने तो आपसे पहले ही कहा है कि हम तुरंत वहां गए और तुरंत हमने यह पैसा दे दिया। अब सैंट्रल टीम वहां जाएगी और बाकी पैसा उसकी रिपोर्ट आने के बाद देंगे।

RE. U.S. PLAN TO HAVE AN F.B.I OFFICE IN INDIA

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Madam, a few days back, there was a report in the Press that the Federal Bureau of Investigation of the U.S.A., the F.B.I., wanted to set up a branch in India. The report further said that the Government was favourably inclined towards the proposal. The report also said that the Government was afraid of the political call-out of that, how the different parties would react to that. Madam, I beg to submit that this move by the F.B.I. to set up shop in India is dangerous and the Government must reject it. Even within the U.S.A., the F.B.I. is known to be almost above the law a kind of 'state within a state'. For such a powerful and dangerous organisation to be allowed to set up an office in India is not going to be safe for the country.

Madam, a few years ago, the Air India plane Kanishka blew up over the Atlantic and hundreds of precious lives were lost. Subsequently, the Canadian Government found that the anti-national terrorist elements which had blown up Kanishka had been trained in a school in the U.S.A. run by an F.B.I. agent. This F.B.I. agent made it public that he had informed his superiors about it. But the F.B.I. authorities never thought it proper either to inform India or to inform Canada that a serious act of sabotage was afoot. It is an agency which acted so